

Daily Current Affairs

Date : 03 June, 2026



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	7.19 करोड़ ABHA ID के साथ राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर
2.	'एकीकृत क्लस्टर विकास योजना' के तहत 7 कॉमन फैसिलिटी सेंटर
3.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. योगेश शर्मा : राजस्थान राजस्व मंडल में राजस्व-प्रथम सदस्य 2. पंकज शर्मा : उत्तर-पश्चिम रेलवे (NWR) के नए महाप्रबंधक 3. 'ऑपरेशन स्माइल' 4. श्रीलंका में जयपुर फुट के दो स्थायी केंद्र स्थापित 5. एक्सपोर्टर्स डायरेक्ट्री - 2026 6. खेत बचाओ अभियान - 2026 7. शहीद हवलदार गजराज सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण
4.	माजुली द्वीप
5.	समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात 2025-26 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।
6.	भूल जाने का अधिकार
7.	महा जल मिशन
8.	परियोजना उदयक
9.	कनाडा-भारत व्यापार और निवेश मंच
10.	भारत-म्यांमार संबंध

-:1:-



UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213



राजस्थान परिदृश्य



7.19 करोड़ ABHA ID के साथ राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर

चर्चा में क्यों?

- 1 जून, 2026 तक के आँकड़ों के अनुसार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत आभा (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट - ABHA) आईडी बनाने में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। (स्रोत - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)

➤ राजस्थान ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

➤ लगभग 7 करोड़ 19 लाख खातों के साथ, देश में दूसरे स्थान पर

➤ डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र से, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली हो रही सशक्त



मुख्य बिन्दु:

- सबसे ज़्यादा ABHA IDs बनाने वाले शीर्ष - 5 राज्य:-

रैंक	राज्य	ABHA कार्ड
1st	उत्तर प्रदेश	15.3 करोड़+
2nd	राजस्थान	7.19 करोड़+
3rd	महाराष्ट्र	7.10 करोड़+
4th	बिहार	6.3 करोड़+
5th	पश्चिम बंगाल	5.9 करोड़+

- जून, 2026 तक देशभर में 90 करोड़ से अधिक ABHA IDs बनाई जा चुकी हैं।

---2---

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM)

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 27 सितंबर, 2021 को लॉन्च किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सक्रिय सहयोग के माध्यम से एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM), जिसे पूर्व में 'राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन' के रूप में जाना जाता था, का उद्देश्य कुशल, सुलभ, समावेशी, किफायती, समयबद्ध और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक (Universal) स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करना है।

आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (ABHA)

- ABHA 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' का भाग है।
- **सम्बन्धित मंत्रालय :** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।
- **उद्देश्य :** नागरिकों के स्वास्थ्य अभिलेखों का केंद्रीकृत, सुरक्षित एवं डिजिटल संग्रह सुनिश्चित करना।
- राजस्थान में दिसंबर, 2025 तक 6.52 करोड़ से अधिक ABHA IDs बनाई जा चुकी है।
- **फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:**
- राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाने के लिए 'स्वास्थ्य सेवा का अधिकार अधिनियम, 2023' क्रियान्वित किया जा रहा है।
- हाल ही में, राजस्थान में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अंतर्गत सभी 41 जिलों में एक राजकीय एवं एक निजी स्वास्थ्य संस्थान का चयन किया गया है, जिन्हें 'मॉडल फैसिलिटी' के रूप में विकसित किया जाएगा।
- मॉडल फैसिलिटी के रूप में चयनित इन संस्थानों को स्पेशल सपोर्ट देकर डिजिटल किया जाएगा और इनमें एंड-टू-एंड ABDM के सभी कॉम्पोनेन्ट; जैसे - स्कैन एंड शेयर, ABDM कम्प्लायंट हेल्थ मैनेजमेंट इंफोर्मेशन सिस्टम एडॉप्शन, हेल्थकेयर फैसिलिटी रजिस्ट्री और हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री करवाकर, सभी मरीजों की ABHA ID बनाकर हेल्थ रिकॉर्ड लिंक किया जाएगा।

‘एकीकृत क्लस्टर विकास योजना’ के तहत 7 कॉमन फैसिलिटी सेंटर

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान सरकार द्वारा ‘एकीकृत क्लस्टर विकास योजना’ के तहत 7 कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे।



2 साल
नव उत्थान - नई पहचान
बढ़ता राजस्थान - हुमाय राजस्थान



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

एकीकृत क्लस्टर विकास योजना

एमएसएमई और हस्तशिल्पियों को मशीन व प्रशिक्षण हेतु
58 करोड़ रुपये का अनुदान

- 7 जिलों में बनेंगे कॉमन फैसिलिटी सेंटर, 100 से अधिक एमएसएमई इकाइयों का मिलेगा लाभ



मुख्य बिन्दु:

- 7 कॉमन फैसिलिटी सेंटर : भरतपुर, हनुमानगढ़, फलौदी, कोटपूतली-बहरोड़, बालोतरा, दौसा और जयपुर।

--:4::--

Daily Current Affairs

 Date : 03 June, 2026



- इन कॉमन फैसिलिटी सेंटर में आधुनिक मशीनें स्थापित की जाएंगी, जिनका उपयोग वहाँ की 100 से अधिक लघु और सूक्ष्म श्रेणी की औद्योगिक इकाइयाँ कर सकेंगी।

एकीकृत क्लस्टर विकास योजना:-

- **शुरुआत :** राज्य सरकार द्वारा एकीकृत क्लस्टर विकास योजना को दिसंबर, 2024 में अधिसूचित किया गया। जनवरी, 2025 में इस योजना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए।
- इस योजना के तहत 3 वर्षों में राज्य में हथकरघा, हस्तशिल्प और MSMEs क्षेत्र के 50 क्लस्टर विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- **पात्रता :** एक ही स्थान पर कार्यरत कम से कम 20 समान उत्पादन वाले MSMEs उद्योग।
- योजना का लाभ लेने के लिए 10 से अधिक इकाइयों को एक अलाभकारी कंपनी बनाकर आवेदन करना आवश्यक है।
- **अनुदान :** राज्य सरकार द्वारा उत्पादन, जाँच, भंडारण, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सहयोग के लिए कुल लागत का 80 फीसदी तक अनुदान।
- **नोट :** हस्तशिल्पियों और बुनकरों के प्रशिक्षण के लिए 100 फीसदी तक अनुदान।

-:5:-



✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़										
1.	योगेश शर्मा : राजस्थान राजस्व मंडल में राजस्व-प्रथम सदस्य - हाल ही में, राजस्थान न्यायिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और जिला जज योगेश शर्मा को राजस्थान राजस्व मंडल (अजमेर) में राजस्व-प्रथम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। राजस्व मण्डल का प्रशासनिक ढाँचा :- - इसका अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा का मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी होता है, जिसकी सहायता हेतु 20 सदस्य होते हैं। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा व राजस्व मामले के विशेषज्ञ वकीलों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। <table><tr><th>सदस्य</th><th>योग्यता</th></tr><tr><td>भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग</td><td>राजस्थान कैडर का अधिकारी, जो कम से कम 16 वर्ष राज्य में कार्य कर चुका हो।</td></tr><tr><td>राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग</td><td>राजस्थान HC का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो।</td></tr><tr><td>अधिवक्ता</td><td>राजस्थान HC का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो।</td></tr><tr><td>राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग</td><td>सुपर टाइम स्केल श्रृंखला।</td></tr></table> अन्य महत्वपूर्ण तथ्य : - राजस्थान राजस्व विभाग के प्रथम अध्यक्ष : बृजचन्द शर्मा। - वर्तमान अध्यक्ष : अजिताभ शर्मा। - प्रथम राजस्व दिवस : 15 अक्टूबर, 2020 - राजस्थान राजस्व परिषद् का गठन : वर्ष 1953 में।	सदस्य	योग्यता	भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग	राजस्थान कैडर का अधिकारी, जो कम से कम 16 वर्ष राज्य में कार्य कर चुका हो।	राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग	राजस्थान HC का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो।	अधिवक्ता	राजस्थान HC का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो।	राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग	सुपर टाइम स्केल श्रृंखला।
सदस्य	योग्यता										
भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग	राजस्थान कैडर का अधिकारी, जो कम से कम 16 वर्ष राज्य में कार्य कर चुका हो।										
राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग	राजस्थान HC का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो।										
अधिवक्ता	राजस्थान HC का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो।										
राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग	सुपर टाइम स्केल श्रृंखला।										

2.	पंकज शर्मा : उत्तर-पश्चिम रेलवे (NWR) के नए महाप्रबंधक ■ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस (IRSEE) के वर्ष 1989 बैच के अधिकारी पंकज शर्मा को उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) का नया महाप्रबंधक (GM) नियुक्त किया। ■ उत्तर-पश्चिम रेलवे (NWR) भारतीय रेलवे के 19 प्रमुख रेलवे ज़ोन में से एक है, जिसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। इस ज़ोन की स्थापना 1 अक्टूबर, 2002 को की गई थी। ■ इसका नेटवर्क मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात में विस्तृत है।
3.	'ऑपरेशन स्माइल' ■ राजस्थान पुलिस का 'ऑपरेशन स्माइल' मुख्य रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, उनके अधिकारों का संरक्षण करने और उन्हें कानूनी तौर पर जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा एक विशेष राज्यव्यापी अभियान है। ■ इस अभियान के तहत पुलिस थानों में विशेष बैठकें आयोजित की जाती हैं।
4.	श्रीलंका में जयपुर फुट के दो स्थायी केंद्र स्थापित ■ भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (BMVSS) ने हाल ही में श्रीलंका में जयपुर फुट के दो स्थायी केंद्र स्थापित किए। ■ कोलंबो केंद्र : श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 'कोलंबो फ्रेंड-इन-नीड सोसाइटी' (CFINS) के सहयोग से संचालित। ■ जाफना केंद्र : उत्तरी प्रांत का केंद्र 'जाफना जयपुर सेंटर फॉर डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन' (JJCDR) के परिसर में स्थापित। ■ नोट : मई, 2026 में त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में भी 'जयपुर फुट प्रोस्थेटिक लिम्ब' केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर द्वारा किया गया।

Daily Current Affairs

Date : 03 June, 2026



5.	एक्सपोर्ट्स डायरेक्ट्री - 2026 - हाल ही में, राजस्थान के मुख्य सचिव ने राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (RCCI) द्वारा तैयार की गई 'राजस्थान एक्सपोर्ट्स डायरेक्ट्री - 2026' का आधिकारिक विमोचन किया। - एक्सपोर्ट्स डायरेक्ट्री - 2026 निर्यात व्यापार से जुड़े पेशेवरों, खरीदारों और सप्लायर्स के लिए एक महत्वपूर्ण डेटाबेस है।
6.	खेत बचाओ अभियान - 2026 संचालन : राज्यव्यापी संचालन 1 से 30 जून, 2026 तक। संचालनकर्ता : राजस्थान कृषि विभाग और केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। मुख्य उद्देश्य : मिट्टी की सेहत सुधारना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना।
7.	शहीद हवलदार गजराज सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण हाल ही में, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्वा ने बीकानेर के उदयरामसर में CRPF के शहीद जवान हवलदार गजराज सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया।

SERVICES

--8--



UTKARSH CLASSES | support@utkarsh.com | : 9829 213 213



भूगोल एवं भू-विज्ञान



माजुली द्वीप

(स्रोत: DD NEWS)



चर्चा में क्यों?

- बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में माजुली द्वीप के लगभग 4,000 वर्षों के जलवायु, वनस्पति और नदी की गतिशीलता का पुनर्निर्माण किया गया है।



मुख्य बिन्दु:

माजुली द्वीप

- माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- माजुली ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित एक अनूठा जलोढ़ द्वीप है, जो लगभग 875 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

--9--

Daily Current Affairs

 Date : 03 June, 2026



- यह उत्तर-पश्चिम में सुबनसिरी और उसकी सहायक नदियों (रंगा नदी, डिक्लॉंग, डुबला, चिची और टुनी आदि), उत्तर-पूर्व में खेरकटिया सुती (ब्रह्मपुत्र की अतिरिक्त जलधारा), तथा दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम में ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है।
- इसके भूभाग में जलोढ़ मैदान, घुमावदार जलधाराएँ, आर्द्रभूमि (बील) और चापोरी के नाम से जानी जाने वाली नदी की रेत की पट्टियाँ शामिल हैं।
- यह द्वीप श्रीमंत शंकरदेव द्वारा स्थापित नव-वैष्णव संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र है।
- इसमें लगभग 30 सत्रा (वैष्णव मठ) स्थित हैं, जो धर्म, संस्कृति, शिक्षा और सामुदायिक प्रशासन के केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं।
- प्रमुख सत्रों में औनियाती सत्र, कमलाबाड़ी सत्र, गरमुर सत्र और दखिनपत सत्र शामिल हैं।
- यह मिसिंग, देओरी और सोनोवाल कचारी जनजातियों सहित कई स्वदेशी आदिवासी समुदायों का घर है।
- इसे 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया था।



आर्थिक घटनाक्रम



समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात 2025-26 में रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया।

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के समुद्री खाद्य निर्यात ने मात्रा और मूल्य दोनों ही दृष्टि से सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया।



मुख्य बिन्दु:

- भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में जमे हुए झींगे का दबदबा बना रहा, जो कुल निर्यात आय का लगभग दो-तिहाई हिस्सा है।
- अमेरिका भारतीय फ्रोजन झींगा का सबसे बड़ा आयातक बना रहा, उसके बाद चीन का स्थान रहा।
- अन्य प्रमुख गंतव्यों में यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया, जापान, मध्य पूर्व और कई अन्य देश शामिल थे।
- फ्रोजन मछली निर्यात की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी के रूप में उभरी, जबकि सूखे समुद्री खाद्य उत्पाद तीसरे स्थान पर रहे।
- निर्यात के प्रमुख गंतव्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद चीन और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं।
- वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान समुद्री खाद्य निर्यात कार्गो को संभालने वाले शीर्ष तीन बंदरगाहों के रूप में विशाखापत्तनम, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और कोच्चि उभरे।

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

भूल जाने का अधिकार

(स्रोत: ECONOMIC TIMES)

चर्चा में क्यों?

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'लक्ष वीर सिंह यादव बनाम भारत संघ और अन्य' वाद में एक व्यक्ति के 'भूल जाने के अधिकार' को अनुच्छेद 21 के तहत 'निजता का अधिकार' मूल अधिकार का अभिन्न अंग माना है।



मुख्य बिन्दु:

- भूल जाने का अधिकार:** यह वह अधिकार है जिसके तहत कोई व्यक्ति अपनी ऐसी व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक पहुँच से हटाने या उस तक पहुँच सीमित करने की माँग कर सकता है, जिसका अब कोई वैध या आवश्यक उद्देश्य नहीं रह गया हो।

निर्णय के प्रमुख बिंदु

- यह विस्तृत सिद्धांत निर्धारित करता है कि न्यायालय के रिकॉर्ड में नामों को कब छिपाया जा सकता है।

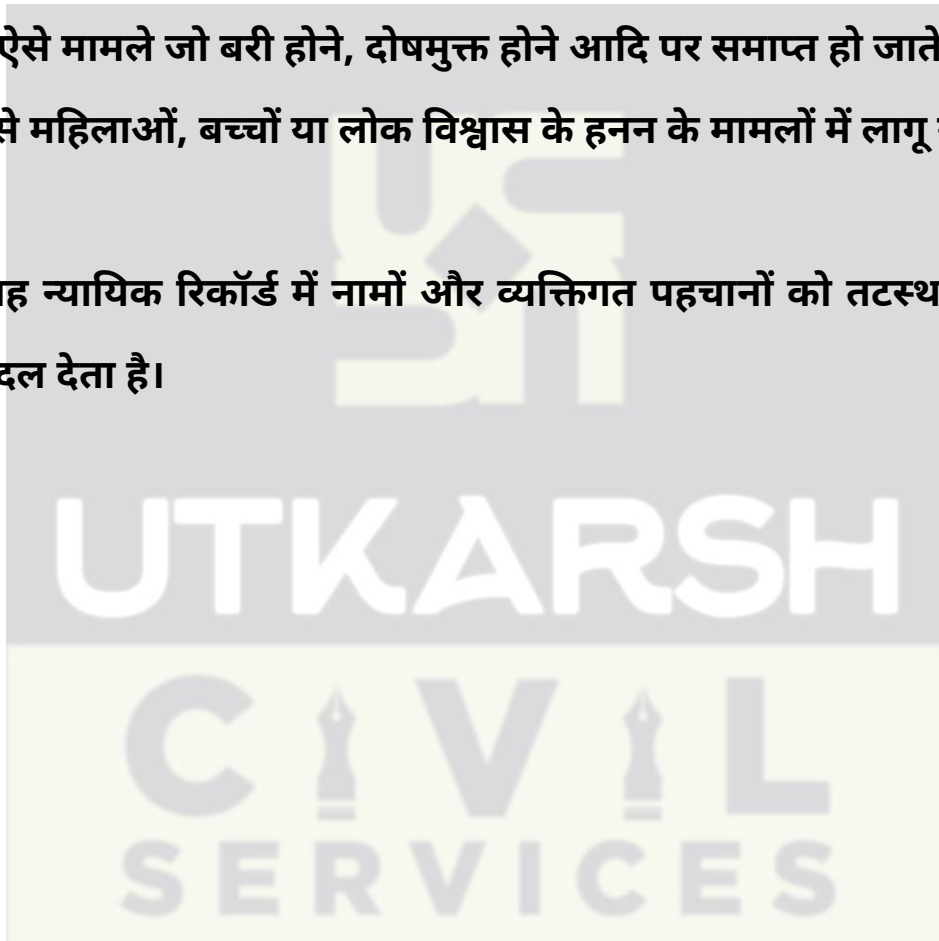
-:12:-

Daily Current Affairs

 Date : 03 June, 2026



- **डी-इंडेक्सिंग:** इसमें किसी व्यक्ति का नाम सर्च इंजन के लिए उपयोग होने वाली कुंजी के रूप में हटा दिया जाता है, लेकिन संबंधित रिकॉर्ड को मिटाया नहीं जाता। इससे उस जानकारी तक नाम के आधार पर खोज करके पहुँचना कठिन हो जाता है, जबकि रिकॉर्ड अपने मूल स्रोत पर उपलब्ध रह सकता है।
- **अनुप्रयोग:** ऐसे मामले जो बरी होने, दोषमुक्त होने आदि पर समाप्त हो जाते हैं।
- **अपवाद:** इसे महिलाओं, बच्चों या लोक विश्वास के हनन के मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है।
- **मास्किंग:** यह न्यायिक रिकॉर्ड में नामों और व्यक्तिगत पहचानों को तटस्थ चिह्नों (जैसे- XYZ) से बदल देता है।



योजनाएँ एवं नीतियाँ

महा जल मिशन

(स्रोत: डीडी न्यूज़)

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और जल शक्ति मंत्री ने जल क्षेत्र में नवाचार को गति देने के लिए 200 करोड़ रुपये की 'महा जल मिशन' का शुभारंभ किया।



मुख्य बिन्दु:

- MAHA (मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई-इम्पैक्ट एरियाज़) जल मिशन एक उच्च प्राथमिकता वाला राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसे मौलिक अनुसंधान और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

शामिल संगठन:

- अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन: भारत में अनुसंधान वित्तपोषण को लोकतांत्रिक बनाने और सुव्यवस्थित करने वाली प्रमुख संस्था।
- जल शक्ति मंत्रालय: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन के लिए नोडल मंत्रालय।
- अंतरिक्ष विभाग: जल मानचित्रण और मूल्यांकन के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी और भू-स्थानिक डेटा उपलब्ध कराना।

प्रमुख विशेषताएँ:

- बहुविषयक संघ: इसमें विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संगठनों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और उद्योग भागीदारों का मिश्रण भाग ले सकता है।

-:14:-

Daily Current Affairs

 Date : 03 June, 2026



पाँच प्राथमिकता वाले विषय:

- जल संसाधन मूल्यांकन और सतत प्रबंधन।
- पेयजल (गुणवत्ता और उपलब्धता)।
- जल की गुणवत्ता और पारिस्थितिक स्वास्थ्य।
- जल उपयोग दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और अनुकूलन।



-:15:-



UTKARSH CLASSES |  support@utkarsh.com |  : 9829 213 213

परियोजना उदयक

(स्रोत: PIB)

चर्चा में क्यों?

- बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) ने असम के डूमडूमा में परियोजना उदयक का 37वाँ स्थापना दिवस मनाया।



मुख्य बिन्दु:

- परियोजना उदयक, सीमा सड़क संगठन की एक विशेष क्षेत्रीय शाखा है, जिसे पूर्वोत्तर भारत के सबसे दूरस्थ और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण इलाकों में विशाल सड़क नेटवर्क के विकास और रखरखाव का कार्य सौंपा गया है।
- **प्रारंभ:** इस परियोजना की स्थापना 1989 में हुई थी (और 2026 में इसके संचालन के 37 वर्ष पूरे हो जाएंगे)।
- **संगठन:** यह बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) के तहत काम करता है, जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।

--:16:--

प्रमुख विशेषताएँ और उत्तरदायित्व के क्षेत्र:

- **भौगोलिक कवरेज:** यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों और असम के कुछ हिस्सों के लिए जिम्मेदार है।
- **इसके प्राथमिक कार्यक्षेत्र में जिले:**
 - अंजॉ, लोहित और दिबांग घाटी।
 - लोंगडिंग, तिराप और चांगलांग।
- **रणनीतिक सीमा प्रबंधन:** यह दो संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ सड़क अवसंरचना का प्रबंधन करता है:
 - चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी)।
 - भारत-म्यांमार सीमा
- **नागरिक-सैन्य एकीकरण:** यह परियोजना नियमित रूप से सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित करती है, जिसमें दूरस्थ सीमावर्ती गाँवों में रहने वाली स्थानीय आदिवासी आबादी के लिए चिकित्सा शिविर, स्वच्छता अभियान और सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं।



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



कनाडा-भारत व्यापार और निवेश मंच

(स्रोत: PIB)



चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कनाडा में अब तक के सबसे बड़े भारतीय व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने 'कनाडा-भारत व्यापार और निवेश मंच' की शुरुआत की तथा वर्ष 2026 के अंत तक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।



मुख्य बिन्दु:

कनाडा-भारत व्यापार और निवेश मंच 2026 की मुख्य विशेषताएँ

- **व्यापार और निवेश मंच की शुरुआत:** 'कनाडा-भारत व्यापार और निवेश मंच' को बिज़नेस लीडर्स को एक साथ लाने, नवीन व्यावसायिक साझेदारियों को बढ़ावा देने तथा द्विपक्षीय समन्वय को बढ़ाने के लिये एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में शुरू किया गया था।

--:18:--

Daily Current Affairs

 Date : 03 June, 2026



- **CEPA वार्ताओं में तेज़ी लाना:** दोनों देश एक व्यावहारिक दृष्टिकोण पर सहमत हुए हैं, जिसके अंतर्गत आसानी से प्राप्त होने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे भारत के लिये कृषि और डेयरी) में रियायतों की तत्काल मांग से बचा जाएगा।
- **व्यापार लक्ष्य:** भारत और कनाडा अपने द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि करने का लक्ष्य रख रहे हैं, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचना है।
- **'टीम कनाडा' ट्रेड मिशन:** कनाडा ने घोषणा की कि वह वर्ष 2026 में भारत में एक 'टीम कनाडा ट्रेड मिशन' का नेतृत्व करेगा, जो भारतीय बाज़ार में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिये कनाडाई व्यवसायों की रुचि का संकेत देता है।
- **सहयोग के रणनीतिक क्षेत्र:** वार्ता में स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, कृषि-खाद्य, उन्नत विनिर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकी और कौशल विकास जैसे पारस्परिक रूप से पूरक क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- मई 2026 में, G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान के अनुरूप, सुरक्षित और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए थे।

भारत-म्यांमार संबंध

(स्रोत: PIB)

चर्चा में क्यों?

- भारत के प्रधानमंत्री और म्यांमार के राष्ट्रपति ने आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की, जिनमें AI और अंतरिक्ष जैसे विषय शामिल थे।



मुख्य बिन्दु:

- दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए रुपया-क्यात व्यापार निपटान तंत्र (2024 में चालू) की सतत संवृद्धि का भी स्वागत किया।

भारत-म्यांमार संबंधों का महत्व:

- **भू-रणनीतिक:** म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर (MAHASAGAR) जैसी नीतियों के केंद्र में स्थित है।

-:20:-

Daily Current Affairs

 Date : 03 June, 2026



- **कनेक्टिविटी:** क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कालादान मल्टी-मॉडल परियोजना।
- **सुरक्षा:** सीमा पार से होने वाले नृजातीय उग्रवाद (1,643 किमी लंबी सीमा पर) से निपटने तथा पूर्वोत्तर राज्यों में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी (स्वर्णिम त्रिभुज) को रोकने के लिए।
- **सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर:** साझा थेरवाद बौद्ध विरासत आधारित सुदृढ़ ऐतिहासिक संबंध।



-:21:-



UTKARSH CLASSES |  support@utkarsh.com |  : 9829 213 213